World Bank's Conditions for Loan to PFC

1434. DR. RANBIR SINGH:
SHRI RAM NATH KOVIND:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the World Bank has stipulated stringent conditions for the proposed $ 500 million loan to the Power Finance Corporation to lend the same to the State Electricity Boards for restructuring;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose to take any action in this regard; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (d) The proposal of Power Finance Corporation for a loan of US $ 500 Million from the World Bank to on-lend to the State Electricity Boards for restructuring is at a very preliminary stage of discussions between the World Bank, Power Finance Corporation and the Government of India.

Demurrage for Delayed Unloading of Petroleum by IOC

1435. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the Indian Oil Corporation has to pay heavy demurrage, in foreign currency, for delay in unloading of diesel and petroleum at ports due to congestion at ports;

(b) if so, the details of the demurrage amount paid during the current year, month-wise, at each of the ports of the country; and

(c) the steps being taken by Government, in consultation with the Ministry of Surface Transport, for quick unloading of imported diesel and petroleum and to remove decongestion at ports so that imports could be unloaded expeditiously?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI T.R. BALU): (a) to (c) Information is being collected and shall be placed on the Table of the House.

Reducing the Number of Shelterless in Bihar

1436. SHRI S.S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Housing Policy envisages that the State Governments will draw up Action Plans to achieve the goal of reduction in the number of shelterless in the country;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Bihar Govenrment has drawn up such an Action Plan and submitted the same to the Central Govenrment for Central funding; and

(d) if so, what are the details thereof and the reaction of Government thereto;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. U. VENKATESWARLU): (a) and (b) The National Housing Policy envisages that States/UTs will formulate perspective plans of actions and short term plans for time-bound implementation by State and local agencies with the involvement of Central institutions, private and cooperative agencies and build these plans into the Five Year Plans, city and district development plans, etc.

(c) and (d) Government of Bihar has got Action Plan preparead through a research institution. This Action Plan was fully fiunded by Govenrment of India. The draft report was submitted to the State Govt. in July, 1995. The State Government is expected to make use of the report while formulating and implementing the housing schemes to suit their requirements out of their plan funds. No direct Central assistance is given for State plan housing schemes. Howver, HUDCO provides loan assistance for such schemes.

प्राकृतिक संसाधनों संबंधी राष्ट्रीय नीति

1437. **श्री इकबाल सिंह:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उत्पादकता को बढ़ाने के लिए देश में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार ने किन-किन विशेष बातों पर बल दिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के० अलघ): (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना ने माना है बुनियादी संसाधन निधियां अर्थात् ऊर्जा स्रोत, भूमि, जल और अन्य अनिवार्य खनिज, पर्यावरण और पारिस्थितिकी आदि विकास और तुलनात्मक लाभ के लिये क्षमता निर्धारण में महत्वपूर्ण तत्व हैं। विकास परिदृश्य से संबंधित आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में प्राकृतिक संसाधनों पर सामान्य ब्यौरे प्रस्तुत किये गये थे।

यह अनिवार्य है कि जो प्रक्रियायें ऊर्जा के उपयोग की किफायत करती है और कच्ची सामग्री का बर्बादी को बचाती है उन्हें अपनाया जाना चाहिए। योजना में दर्शाई गई और नवीकरण योग्य संसाधन कार्य नीतियों का कार्यान्वयन अपेक्षित है।

प्रोयोगिकी और प्रक्रियायों में परिवर्तन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रकों में ऊर्जा की तेजी को घटाने के लिए उपाय शुरु किए जाने होंगे। अंतर ऊर्जा और बाह्य ऊर्जा एवजियों को इष्टतम बनाना होगा। ऊर्जा के नवीकरण योग्य स्रोतों के उपयोग को अधिकतम करने की ओर मुख्य बल देना होगा। उत्पादन के लिए ऊर्जा खपत कम करने हेतु कार्य कौशल, संरक्षण और मांग प्रबन्धन पर सबसे अधिक जोर देना होगा।

जल उपयोग के क्षेत्र में जल प्रबन्धन को कुशलता में सुधार और सतही और भूमिगत जल के संयुक्त उपयोग, पर्याप्त कायम रखने योग्य अनुरक्षण और किसानों की भागीदारी द्वारा की गई सिंचाई के माध्यम से उपयोग किये गये जल की उत्पादकता को बढ़ाना अनिवार्य है।

खनिज संसाधन नवीकरण योग्य न होने के कारण, खनिज भण्डारों की खोज और अन्वेक्षण और वैज्ञानिक रूप से योजित मांग प्रबनधन दूसरे प्रतिस्थापनों के उपयोग द्वारा इनके लिए अधिक उत्पसाहजनक और सतत् प्रयासों की आवश्यकता होती है।

हिमालय क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज

1438. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम ने हिमालय क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के राजौरी और सरोईसर में, हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी और सरकाघाट में तथा उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल में पेट्रोल की खोज का कार्य कई वर्ष पूर्व आरम्भ किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें से प्रत्येक स्थान पर खोज कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है;

(ग) आज तक प्रत्येक स्थान पर वर्ष-वार कितनी-कितनी राशि खर्च की गई और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) भावी योजनाएं क्या-क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी० आर० बालू): (क) और (ख) जी, हां। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में ओ एन जी सी द्वारा किए गए अन्वेषण कार्य का ब्यौरा निम्नवत है:—

जम्मू और कश्मीर में राजौरी और सुरूईसार क्षेत्रों में अन्वेषण

ओ एन जी सी 1957 से जम्मू और कश्मीर में तेल और गैस का अन्वेषण कर रही है। तृतीयक तराई क्षेत्र में भूगर्भीय, गुरूत्व चुम्बकीय और पारम्परिक भूकम्पीय सर्वेक्षणों सहित भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किए गए। ये सर्वेक्षण कश्मीर घाटी में भी किए गए। भूकंपीय सर्वेक्षण मार्च, 1996 से राजौरी में शुरू किए गए उप-सतही संरचनात्मक आकृति चित्रित करने और संभावनाओं का